

<><><><><><><><>

- झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अस्पताल पहुँचकर अपनी संवेदना व्यक्त की। राज्यसभा की कार्यवाही भी दिनभर के लिए स्थगित की गई।
- श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि सोलह महीनों में ग्यारह लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है।
- द्वीपसमूह के सांसद बिष्णु पद रे ने माउन्ट मणिपुर स्मारक के निर्माण की मांग के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा।
- विद्युत विभाग ने बिजली की कमी के चलते एक महीने की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर लोड शेडिंग की प्रक्रिया शुरू की।

<><><><><><><><>

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल पहुँचकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्री शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि श्री सोरेन का निधन सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने भी अपने संदेश में कहा कि श्री सोरेन ने जनजातीय समुदायों, निर्धन और उपेक्षित लोगों के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रयास किए। श्री मोदी ने श्री सोरेन के परिजनों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आज राज्यसभा की कार्यवाही आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। श्री सोरेन का लंबी बीमारी के बाद आज दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में निधन हो गया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री हरिवंश ने कहा कि शिबू सोरेन एक वरिष्ठ और प्रतिष्ठित जनजातीय नेता थे, उन्होंने जनजाति समुदायों के अधिकारों और उनके उत्थान में प्रमुख भूमिका निभाई थी। श्री सोरेन आठ बार लोकसभा सदस्य चुने गए और तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी।

<><><><><><><><>

श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि रोजगार मेले के तहत पिछले सोलह महीनों में ग्यारह लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। श्री मांडविया ने लोकसभा में कहा कि आर.बी.आई की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में सत्रह करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है। सेवा क्षेत्र में, एन.डी.ए सरकार के कार्यकाल में रोजगार सृजन बढ़कर छत्तीस प्रतिशत हो गया है।

<><><><><><><><>

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए विशेष पंजीकरण अभियान की अवधि पंद्रह अगस्त तक बढ़ा दी है। आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में घर-घर जाकर जागरूकता एवं नामांकन अभियान का उद्देश्य सभी पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं तक पहुंचना और योजना के तहत उनका समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना है। यह योजना गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के बीच पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है और बालिकाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। पी.एम.एम.वी.वाई वेतन में कमी होने की स्थिति में आंशिक मुआवजे के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि माताएं पहले बच्चे के जन्म से पहले और बाद में आराम कर सकें। इस योजना की शुरुआत से लेकर इक्कीस जुलाई, दो हजार पच्चीस तक चार दशमलव शून्य पांच करोड़ से अधिक लाभार्थियों को उनके बैंक अथवा डाकघर खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से उन्नीस हजार अट्ठाईस करोड़ रुपये की राशि का मातृत्व लाभ का भुगतान किया जा चुका है।

<><><><><><><><>

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह सांसद बिष्णु पद रे ने दक्षिण अंडमान में माउंट मणिपुर स्मारक के निर्माण की मांग के सम्बन्ध में गृह मंत्री को पत्र लिखा है। गृह मंत्री श्री अमित शाह को लिखे इस पत्र में दक्षिण अंडमान में उपयुक्त स्थान पर माउंट मणिपुर स्मारक के पुनरुद्धार और निर्माण हेतु कार्रवाई का आग्रह किया गया है। अटठारह सौ इक्यानब्बे के एंग्लो-मणिपुर युद्ध के तेईस बहादुर मणिपुरी स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में माउंट हैरियट का नाम बदलकर कर माउंट मणिपुर कर दिया गया था जिसमें महाराजा कुलचंद्र ध्वज सिंह भी शामिल थे, जिन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान द्वीपों पर निर्वासित कर दिया गया था। सांसद रे ने कहा कि माउंट मणिपुर स्मारक का शीघ्र निर्माण पूर्वोत्तर और अंडमान द्वीप समूह के बीच भावनात्मक और ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करेगा।

<><><><><><><>

केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव की उपस्थिति में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड द्वारा दो महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। पहला समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और ईश्वर-बायोप्लांट्स वेंचर, पुणे, महाराष्ट्र के बीच और दूसरा त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के बीच हस्ताक्षरित किया गया। केंद्रीय मंत्री श्री जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दो हजार सैंतालीस तक एक स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत बनाने का विजन आज हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करता है। मैं इन महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले सभी संस्थानों को बधाई देता हूँ, जो भारत की समृद्ध औषधीय पादप विरासत के संरक्षण और संवर्धन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हैं। पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ एकीकृत करके हम इस महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में सार्थक प्रगति कर रहे हैं। इन दोनों समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का उद्देश्य है एन.एम.पी.बी और ईश्वर-बायोप्लांट्स वेंचर के बीच समझौता ज्ञापन और उक्त संवर्धन विधियों के माध्यम से दुर्लभ, लुप्तप्राय और संकटग्रस्त औषधीय पौधों के जर्म प्लाज्म का संरक्षण और रखरखाव करना।

<><><><><><><>

विद्युत विभाग ने जानकारी दी है कि श्री विजयपुरम और दक्षिण अंडमान क्षेत्रों में एक अगस्त से सुबह चार बजे से रात ग्यारह बजे तक एक महीने की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर लोड शेडिंग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। विभाग के अनुसार बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर बढ़ गया है, जिससे चाथम में पाँच मेगावाट एन.वी.वी.एन पावर प्लांट को बंद करने के कारण बिजली की आपूर्ति में कमी आई है, ताकि उसी स्थान पर एक नए दस मेगावाट बिजली संयंत्र की आगामी स्थापना के लिए साइट को खाली कराया जा सके। फीडरों को फिर से चार्ज करने के दौरान घरेलू और वाणिज्यिक इन्वर्टर चार्जिंग और एक साथ उच्च शक्ति वाले गजलर और अन्य उपकरणों को चालू करने के कारण मांग में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कुल मांग अपेक्षा से अधिक बढ़ रही है। इससे पीक आवर्स के दौरान लगभग आठ से नौ मेगावाट और दिन के समय में लगभग चार से पांच मेगावाट की कमी हो गई है। लोड शेडिंग कार्यक्रम पूरी तरह से अस्थायी है और इसकी अवधि और समय उपलब्ध बिजली उत्पादन और अन्य तकनीकी कारणों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यह कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से तीस दिनों के लिए लागू रहेगा।

<><><><><><><>